

**SHRI S. M. BANERJEE:** Tomorrow, there will be no edition of the *Patriot* also, because the strike is in all the newspaper establishments.

**SHRI SAMAR GUHA (Contai):** That is the reason why he wants a discussion tomorrow, because tomorrow there will be no paper and what happens today will not come out in the papers.

12.23½ hrs.

**ARMY, AIR FORCE AND NAVAL LAW (AMENDMENT) BILL\***

**THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA):** On behalf of Shri Swaran Singh, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950 and the Navy Act, 1957.

**MR. SPEAKER:** The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950 and the Navy Act, 1957."

*The motion was adopted.*

**SHRI M. R. KRISHNA:** I introduce the Bill.

12.24 hrs.

**RICE-MILLING INDUSTRY (REGULATION) AMENDMENT BILL**

—Contd.

**MR. SPEAKER:** The House will now proceed with the further consideration of the following motion moved by Shri Annasahib Shinde on the 26th July, 1968, namely:—

"That the Bill to amend the Rice-Milling Industry (Regulation) Act, 1958, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Shri Tulsidas Jadhav may now resume his speech.

12.24½ hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair.]

**श्री तुलसी दास जाधव (बारामती) :** अध्यक्ष महोदय, यह जो राइस मिलिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन बिल है, उस के ऊपर शुक्रवार के दिन मैं बोल रहा था। उस दिन मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जब पब्लिक सेक्टर में हमारी इंडस्ट्री लगती है और इंडस्ट्री लगाने के लिए भारत ने कबूल किया है, कांस्टीट्यूशन में यह कहा है कि कोओपरेटिव कामनवैलथ के रास्ते पर हमें जाना है, तो यह राइस मिलिंग के बारे में जो यह प्राइवेट मिलिंग चलती है उस को किसी रीति से कोओपरेटिव सेक्टर हो या स्टेट सेक्टर हो, उस में लाना गवर्नमेंट का लाजिमी फर्ज हो जाता है। इस प्ब्लिट से देखा जाय तो उस दिन मैंने कहा था कि जहां डिक्टेटरशिप चलती है वहां किसी न किसी रीति से यह चीज लाने के लिए वह नौकरशाही के तरीके के खिलाफ दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं और प्राइवेट प्रापर्टी अपने काबू में ये कर वह स्टेट की तरह से या कोओपरेटिव सेक्टर की तरह से चलाते हैं। इस रीति से हिन्दुस्तान को भी यह बात करनी होगी और भ्रष्टचन तो है लोगों को साथ से कर चलने की और उस में फिर दिक्कत पैदा होती है कि जो भाई कभी-कभी समाजवाद की तरफ अपना रुख दिखाते हैं, वह जब इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो हिचकिचाते हैं, यह भी अनुभव हम लोगों ने इस हाउस में देखा है। लेकिन कुछ भी हो, यह तो हिन्दुस्तान को करना ही होगा। हमारा यह राइस मिलिंग का काम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काम है। यह जितने मीन्स आफ प्रोडक्शन हैं, यह स्टेट के हों या कोओपरेटिव सेक्टर के दायरे में आयें, इस के वरिपर इस देश में कोई चारा नहीं है। हमारा जो गवर्नमेंट प्रिन्सल है वह जमीन से पैदा हो या और कहीं से, उस में जो, धान, मेज काटन, जूट, गुगर केन और प्राउन्ड नट और माइन्स के और मिनरल्स के जितने नेचुरल वैल्य हैं, उन सभी में यह